

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक २३ सितम्बर, 2015

विषय- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में 01 पद प्रमुख निजी सचिव, 01 पद मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं 01 पद मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के अस्थायी निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश के पत्र सं-222/XXXVI(1)/2014-234/2001 टी०सी० दिनांक 29.09.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में शासनादेश सं०-१९/एक(2)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 01.08.2003 के द्वारा सृजित प्रमुख निजी सचिव के 01 अस्थायी निःसंवर्गीय पद एवं शासनादेश सं०-९८/एक(2)/छत्तीस(1)/2005-234/2001 दिनांक 15.12.2005 तथा शासनादेश सं०-९८(क)/एक(2)/छत्तीस(1)/2005-234/2001 दिनांक 16.12.2005 द्वारा सृजित/संशोधित मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के एक-एक अस्थायी निःसंवर्गीय पद के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, दिनांक 01.03.2015 से दिनांक 29.02.2016 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान सं०-०४ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2014-न्याय प्रशासन-००-आयोजनेतर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00” के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०-१०४ NP/XXVII(5)/2015 दिनांक 16.09.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- २९६०/XXXVI(1)/2015-234 / 2001 ————— तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 3- वित्त अनुभाग-५/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

अज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिला)
अपर सचिव

93-०९-१५